Shri Imran Pratapgarhi;

Demand for direct regular train service connecting Pratapgarh, U.P. to Mumbai

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जनपद गौरवशाली जिला है, इस जिले से बड़ी संख्या में देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई के लिए लोग रेल यात्रा करते हैं। व्यापार के लिए, नौकरी के लिए लाखों लोग मुम्बई से जुड़े हुए हैं।

मेरे जनपद प्रतापगढ़ से मुम्बई के लिए डेली कोई भी ट्रेन नहीं जाती, सिर्फ 'साकेत एक्सप्रेस', जिसका नंबर 22184 एवं 22183 है, जो फैज़ाबाद(अयोध्या) से सप्ताह में दो दिन चलती है और प्रतापगढ़ होकर जाती है। इस कारण से प्रतापगढ़ से मुम्बई यात्रा करने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। माननीय रेलमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि प्रतापगढ़ से प्रारंभ करके मुम्बई के लिए डायरेक्ट डेली ट्रेन चलाई जाये या 'साकेत एक्सप्रेस' को डेली किया जाए, जिससे सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं, बल्कि अन्य जनपदों जैसे सुल्तानपुर और जौनपुर के यात्रियों को भी सुविधा हो।

मैं ख़ुद प्रतापगढ़ जनपद का हूँ, मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूँ, मुझे भी वहाँ से यात्रा करने के लिए इलाहाबाद या लखनऊ जाना पड़ता है। अतः रेलमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अर्जेंट इस मामले का संज्ञान लें और 'साकेत एक्सप्रेस', 22184 और 22183 का संचालन प्रतिदिन कराएँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Imran Pratapgarhi: Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Sanjeev Arora (Punjab), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Muzibulla Khan (Odisha), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala) and Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh).

Now, hon. Shri P. Wilson; 'Demand for amendment in Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) for State Owned Discoms.'

Demand for amendment in the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) for State Owned Discoms

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, it has become commonplace to see power generating companies go into insolvency and liquidation, leaving behind dues of hundreds of crores of rupees to State owned DISCOMs. These gencoms are often set up as SPVs with group companies taking up the Engineering Procurement and